साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 02-08 अक्टूबर 2023 वर्ष-9, अंक-25

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

नीमच में मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश के पहले बायोटेक्नालॉजी पार्क का शिलान्यास

जावद कृषि उपज मंडी को सरकार बनाएगी हाई टेक

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच जिले जावद क्षेत्र के सरवानिया महाराज में 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रदेश के पहले बॉयोटेक्नालॉजी पार्क की शिलान्यास किया। 153 करोड़ 37 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जावद कृषि उपज मंडी को हाईटेक बनाया जाएगा। नीमच मंडी के लिए भी विशेष योजना बनेगी। जावद नीमच माइक्रो एरिगेशन योजना जल्द ही मंजूर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को अश्वस्त करते हुए कहा कि वे चिंतित न हों, सोयाबीन फसल का सर्वे कराकर राहत राशि बांटी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी विकास और जनकल्याण के कार्यों से हम मध्यप्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे।

आठ उच्च स्तरीय प्रयोगशालाएं | मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से नवीन अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पार्क में 8 उच्च स्तरीय प्रयोगशालाएं, इनक्यूबेशन सेंटर होंगे। यह पार्क शोधार्थियों, उद्योगपतियों के लिए नई तकनीकी सुविधाओं का केंद्र बनेगा। इससे जैव तकनीकों के व्यवसायीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, बायोटेक क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर बढ़ेंगे। बायोटेक उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्यमी बायोटेक उत्पाद की कंपनी भी शुरू कर सकेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क शोधार्थियों, उद्योगपतियों के लिए नई तकनीकी सुविधाओं का केन्द्र बनेगा।

किसानों के बच्चे करेंगे अध्ययन | गरीब और किसान के बच्चें भी सर्वसुविधायुक्त स्कूलों में अध्ययन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में सीएम राइज स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। चालीस करोड़ रुपए तक की लागत से बनने वाले इन स्कूलों में लाइब्रेरी, खेल मैदान, प्रयोगशाला, बच्चों को लाने ले जाने व स्मार्ट क्लास की सुविधा होगी।

प्रदेश के जबलपुर, कटनी, रायसेन, नर्मदापुरम जिले में गड़बड़ी उजागर

घोटाले में गड़बड़ी का आंकड़ा बढ़ा, जांच में सामने आया सच

चार जिलों में डेढ़ अरब की 1.81 लाख क्विंटल मूंग में मिलावट

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में किसानों के साथ धोखाधड़ी और समर्थन मूल्य पर खरीदी में अब बड़ा घोटाला सामने आया है। इससे जिलों से लेकर राजधानी भोपाल तक में हड़कंप मच गया है। दरअसल, मूंग की खरीदी में हुई गड़बड़ी का दायरा और बढ़ गया है। जबलपुर के अलावा कटनी, रायसेन और नर्मदापुरम जिले में भी ऐसी गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन चार जिलों की 1.81 लाख क्विंटल से अधिक मूंग को खरीदार ने लेने से मना किया है। इसका मूल्य लगभग डेढ़ अरब रुपए है। इस घोटाले की जांच में अनेक जिम्मेदारों के चेहरों से नकाब उतरने की संभावना है। प्रदेश में 1.81 लाख क्विंटल मूंग में भले ही अधिक मात्रा मूंग की हो, बावजूद इसके यह घोटाला करोड़ों रुपए का ही है। केंद्र की पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत रबी सीजन 2021-22 एवं विपणन वर्ष 2022-23 में भंडारित मूंग को ई नीलामी के जरिए पिपरिया के मेसर्स महेश ट्रेडर्स ने खरीदा था। बोलीकर्ता ने कटनी, जबलपुर, रायसेन एवं नर्मदापुरम जिले में भंडारित मूंग की सम्पूर्ण मात्रा खरीदी थी। जब उसने परीक्षण कराया तो उसमें बड़े पैमाने पर मिलावट का पता चला। यह मामला मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ की दहलीज तक पहुंचा तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। प्रबंध संचालक आलोक कुमार संबंधित चारों जिलों को पत्र जारी कर समिति गठित कर मामले की जांच कराने के निर्देश जारी किए।

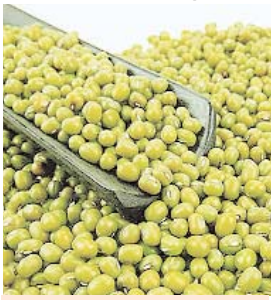

सर्वाधिक मूंग जबलपुर की

दो सालों की रिजेक्ट हुई मूंग में सबसे अधिक 92 हजार क्विंटल जबलपुर जिले की है। इसके बाद नर्मदापुरम की करीब 48 हजार, कटनी की 21 हजार और रायसेन की 19 हजार क्विंटल से अधिक मूंग को रिजेक्ट किया गया। जिले की रिजेक्ट की गई मूंग सिहोरा के एकता वेयर हाउस, जय गोविंद वेयर हाउस, राजपूत वेयर हाउस, सुब्रत वेयर हाउस, सिद्धार्थ वेयर हाउस, आयुष एग्रो वेयर हाउस, महादेव वेयर हाउस, श्रीराज वेयर हाउस, बड़खेड़ा की एमपीडब्ल्यूएलसी गोदाम, भेड़ाघाट का भगवती वेयर हाउस और 14 मयंक वेयर हाउस शामिल हैं।

भिंड कृषि विभाग में 50 लाख का घोटाला

इधर, भिंड जिले के कृषि विभाग में 50 लाख रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया है। कोष एवं लेखा विभाग मध्यप्रदेश भोपाल ने यह घोटाला पकड़ा है। इसके बाद कृषि विभाग के उपसंचालक रामसुजान शर्मा ने प्रथम दृष्टया अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय उपसंभाग भिंड के सहायक ग्रेड-3 रघुकुल राव अर्गल को निलंबित कर दिया है। इस पूरे घोटाले की जांच संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर एवं चंबल संभाग की टीम कर रही है। जिले के सहायक भूमि सरंक्षण अधिकारी कार्यालय उपसंभाग भिंड में रिटायर्ड कर्मचारियों के एरियर सहित अन्य स्वत्तों का पैसा संबंधित कर्मचारियों के खाते में न भेजकर दूसरे खातों में भेजा गया है।

लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा

50 हजार रु. की घूस लेते सरपंच-पंच पति गिरफ्तार

रीवा। लोकायुक्त पुलिस की रीवा टीम ने शहडोल जिले की ग्राम पंचायत मैकी के सरपंच मग्घू बैगा और महिला पंच राबिया के पति मोहम्मद सलीम को एक चाय की दुकान में 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि अहमद शाह शिकायत की गई थी कि पंचायत मैकी में उसके द्वारा स्टाप डैम का निर्माण कराने के लिए मटेरियल की सप्लाई की। अब स्टाप डैम का निर्माण करने की अनुमति देने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। उससे एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। काफी आरजू-मिन्नत किए जाने पर रिश्वत की रकम घटाकर 80 हजार रुपए की गई। इसमें से पचास हजार रुपए लेते सरपंच और पंच पति को पकड़ा गया।

स्मृति शेष | एमएस स्वामीनाथन का निधनः 60 के दशक में गेहूं के हाई क्वालिटी के बीज किए थे विकसित

अकाल देख कृषि में आए, फिर बदली किसानों की जिंदगी और बन गए हरित क्रांति के जनक

नई दिल्ली/भोपाल। जागत गांव हमार

भारत में कृषि क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन नहीं रहे। 98 साल के स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन हो गया। देश को अकाल से उबारने और किसानों को मजबूत बनाने वाली नीति बनाने में उन्होंने अहम योगदान निभाया था। उनकी अध्यक्षता में आयोग भी बनाया गया था जिसने किसानों की जिंदगी को सुधारने के लिए कई अहम सिफारिशें की थीं। स्वामीनाथन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। गौरतलब है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। इसके बाद स्वामीनाथन ने तय किया कि देश में खाने की कमी नहीं हो

इस उद्देश्य से कृषि की पढ़ाई की। 1944 में उन्होंने मद्रास एग्रीकल्चरल कॉलेज से कृषि विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की।

कृषि को अपनाया- 1947 में वह आनुवंशिकी और पादप प्रजनन की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में (आईएआरआई) आ गए। उन्होंने 1949 में साइटोजेनेटिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपना शोध आलू पर किया। हालांकि वह सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में शामिल हुए और भारतीय पुलिस सेवा में उनका चयन हुआ। लेकिन स्वामीनाथन ने पुलिस सेवा को छोड़कर नीदरलैंड जाना सही समझा। 1954 में वह भारत आ गए और यहीं कृषि के लिए काम करना शुरू कर दिया।

भारत में हरित क्रांति के अगुआ बने

एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुआ माना जाता है। वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म की पहचान की। इसके कारण भारत में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। स्वामीनाथन को उनके काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पद्मश्री (1967), पद्मभूषण (1972), पद्मविभूषण (1989), मैग्सेसे पुरस्कार (1971) और विश्व खाद्य पुरस्कार (1987) महत्वपूर्ण हैं।

-ओलावृष्टि की राहत चहेतों के खाते में डलवाई

-किसान वंचित: तीन पटवारियों पर केस दर्ज

-वर्ष 2020 में की थी शिकायत, अब कार्रवाई

भिंड के गोहद में फसल क्षतिपूर्ति घोटाला उजागर

भिंड/गोहद। जागत गांव हमार

ओलावृष्टि की राशि किसानों को न देकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने चहेतों के खाते में राशि डलवाए जाने के मामले में गोहद पुलिस ने तीन पटवारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया। ऐसे में पूर्व में फसल क्षतिपूर्ति को लेकर आई शिकायतों को लेकर अफसरों ने निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्व विभाग में हड़कंप मचा है।

छह अगस्त 2021 में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद को तत्कालीन पटवारी खरौआ संजीव दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर प्रतिवेदन प्रेषित किया। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि जांच समिति के प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन पटवारी संजीव दीक्षित के द्वारा ग्राम माधौगढ़ व कीरतपुरा में वर्ष 2020 में हुई ओलावृष्टि राहत राशि को जानबूझकर ओलावृष्टि से पीड़ित कृषकों के स्थान पर अन्य ग्रामों के संबंधित व्यक्तियों के बैंक खाते के खाते में डलवा दी गई है।

फर्जी दस्तावेज कराए तैयार

ओलावृष्टि से गोहद के जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई थी। उन्हें फसल क्षतिपूर्ति राशि न दिलाकर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर तीनों पटवारियों ने अपने चहेतों के खाते में रुपये डलवा दिए थे। जब पीड़ित किसानों ने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की, तब जाकर यह मामला सामने आया। तीन साल बाद अब संबंधित पटवारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

आवेदनों के आधार पर शुरू होगी जांच

गोहद तहसील में फसल क्षतिपूर्ति घोटाला सामने आने के बाद प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले की सभी तहसीलों में ओलावृष्टि राशि न मिलने की शिकायतों पर गंभीरता से जांच कराए जाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

ओलावृष्टि मुआवजा वितरण में पटवारियों ने गड़बड़ी की थी। साथ ही तहसील में फर्जी नियुक्ति मामले में कर्मचारियों पर एफआइआर दर्ज कराई गई है।

नरेश शर्मा,
तहसीलदार, गोहद

सूची भी प्रस्तुत की गई

साथ ही जिन लोगों के खाते में रुपये डलवाए गए, उसकी एक सूची भी प्रस्तुत की गई। इसके बाद गोहद तहसीलदार द्वारा 31 अगस्त 2021 को एक बार फिर से अनुविभागीय अधिकारी गोहद को प्रतिवेदन भेजा गया। जिसमें लेख किया गया कि छह अगस्त 2021 को पूर्व में आपको प्रतिवेदन भेजा गया था। उक्त प्रतिवेदन में ग्राम भौनपुरा, चिराई, बीलोनी, पडराई के कृषकों के लिए स्वीकृत राशि का संबंधितों को भुगतान संबंधी उल्लेख किया जाना छूट गया था। अत: संशोधित प्रतिवेदन तैयार कर लेख है कि ग्राम माधोग, कीरतपुरा, भौनपुरा, पडराई, बीलोनी, चिराई के कृषकों को स्वीकृत ओलावृष्टि की राहत राशि को ग्राम चक कनीपुरा, खरौआ, छरेटा के व्यक्तियों के खातों में हुई त्रुटिपूर्ण भुगतान की जांच के लिए गठित राजस्व निरीक्षक व पटवारी के द्वारा प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से सहमत होते हुए तत्कालीन पटवारी संजीव दीक्षित के द्वारा ग्राम माधौगढ़ व कीरतपुरा, रामनिवास लोहिया पटवारी के द्वारा ग्राम भौनपुरा, पड़राई एवं संजय जरारिया के द्वारा ग्राम बीलोनी व चिराई में वर्ष 2020 में हुई ओलावृष्टि राहत राशि को जानबूझकर संबंधित पीड़ित कृषकों के स्थान पर अन्य ग्रामों के संबंधित व्यक्तियों के बैंक खाते की सूची प्रस्तुत कर भुगतान कराया जाना पाया गया है। उक्त कृत्य गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में है। अत: तत्कालीन पटवारी सजीव दीक्षित, रामनिवास लोहिया एवं संजय जरारिया के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के लिए प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। इसके बाद 24 सितंबर को तीनों पटवारियों के खिलाफ गोहद थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

पांच अक्टूबर तक होंगे पंजीयन

समर्थन मूल्य पर किसानों की धान खरीदेगी सरकार

इंदौर। जागत गांव हमार

जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए पंजीयन शुरू किए गए हैं। पांच अक्टूबर तक सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक पंजीयन होगा। पंजीयन के लिए किसानों द्वारा स्वयं के मोबाइल अथवा कंप्यूटर, ग्राम पंचायत में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समिति पर फ्री पंजीयन तथा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कामन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्रों पर निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित सायबर कैफे पर 50 रुपये का शुल्क जमा करवाकर पंजीयन करवा सकते हैं। धान बेचने वाले सिकमी, बटाईदार एवं वनपट्टावारी किसानों के पंजीयन सहकारी समिति, सहकारी विपणन सहकारी संस्था के केंद्रों पर किए जाएंगे। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा, जबकि भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। पंजीयन के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन उससे लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जाएगा। किसान के परिवार में जिन सदस्यों के नाम भूमि होगी, वे सभी अपना पृथक-पृथक पंजीयन कराएंगे। किसान की भूमि यदि अन्य जिले में है, तो उस जिले में पंजीयन कराया जाएगा। इंदौर जिले में अलग-अलग स्थानों पर भूमि होने पर एक ही केंद्र पर सभी भूमियों का पंजीयन होगा।

यहां होंगे धान खरीदी के पंजीयन

धान के पंजीयन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र एमपी किसान एप, एमपी आनलाइन कियोस्क, कामन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, निजी व्यक्ति यों द्वारा संचालित सायबर कैफे पर किया जाएगा। कृषकों को अपनी सुविधा के अनुसार, पांच अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पंजीयन करना होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात पंजीयन किया जाना संभव नहीं होगा।

पशु बांझपन निवारण शिविर एवं किसान संगोष्ठी आयोजित

बड़वानी। जागत गांव हमार

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विवि के कुलपति डॉ. सीता प्रसाद तिवारी के मार्गदर्शन एवं पशु चिकित्सा एवं पशुपालन कॉजेल के अधिष्ठाता डॉ. बीपी शुक्ला की अध्यक्षता में कॉजेल, पशुपालन एवं डेयरी विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में पशु बांझपन निवारण शिविर एवं किसान संगोष्ठी का आयोजन जिला बड़वानी के तलून में कृषि विज्ञान केन्द्र बजट्टा खुर्द में किया गया। शिविर तथा संगोष्ठी में 255 पशुपालकों ने भाग लिया। शिविर के समन्वयक डॉ. आरके बघेरवाल डयरेक्टर ने बताया कि यह संगोष्ठी एवं शिविर पशु जागृति अभियान केंद्र सरकार के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. दीपक गांगिल ने पशुपालकों से कहा कि पशुपालन को व्यवसाय के रूप में लेने की जरूरत है। उप संचालक डॉ. सीके रत्नावत एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के संचालक डॉ. बड़ोदिया ने भी पशुपालकों को संबोधित किया। संगोष्ठी में डॉ. अशोक पाटील, डॉ. नवलसिंह रावत, डॉ. पवन माहेश्वरी तथा डॉ. पुष्कर शर्मा ने पशुपालन के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राजेशचन्द्र पाटीदार ने किया। इस अवसर पर विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाइयों का भी वितरण किया गया। विभिन्न ग्रामों के प्रगतिशील पशुपालक रमेश राठौड़, जगदीश, हीरा मुकाती, कोकिल जाट, हरिराम राठौड़ आदि ने भाग लिया।

मप्र गौ-संवर्धन बोर्ड की कार्य-परिषद की बैठक

गौशालाओं की गायों के भरण-पोषण के लिए राज्य सरकार ने जारी किए 52 करोड़ रुपए

भोपाल। जागत गांव हमार

मप्र गौ-संवर्धन बोर्ड की कार्यपरिषद की बैठक भोपाल में हुई। बैठक में प्रदेश की गौशालाओं में संरक्षित गौवश के भरण पोषण की द्वितीय त्रेमास की राशि रुपए 52 करोड़ जिला समितियों को जारी की गई है। जबलपुर, मदसौर और रायसेन जिलों से गौवंश वन्य विहार प्रारम्भिक आवश्यक निर्माण कार्य के लिए राशि जारी की गई है।

प्राय: देखने में आता है की हारवेस्टर के उपयोगों से खेतों में कटाई के पश्चात शेष नरवाई जला दी जाती है। जिससे पर्यावरण को नुकसान एवं भूमि की उर्वरकता में कमी आती है। गौवंश को चारा भूसा भी काफी मंहगी दरों पर उपलब्ध हो पाता है। उक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कृषि अभियांत्रिकी विभाग एवं गौ-संवर्धन बोर्ड की सहभागिता से गौशालाओं की मांग एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार 62 गौशालाओं को भूसा निर्माण के लिए स्ट्रॉरीपर क्रय के लिए आर्थिक सहायता दी गई। जिससे गौशालाएं खेतो में नरवाई से भूसा तैयार कर सके। केन्द्र सरकार की गोबरधन योजना के माध्यम से एकीकृत गोबर गैस संयंत्र निर्माण के लिए चयनित 07 गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट की स्थापना की जा रही है। जिसमें से 3 गौशालाएं उप जेल ग्राम राजोदा जिला देवास, रामसुनाम गौवंश सेवाधाम जिला सतना एवं जरा धाम गो अभयारण्य जिला दमोह में निर्मित संयंत्र सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का उपयोग गैस ईंधन के रूप में स्थानीय रसोई में तथा शेष ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा रहा है।

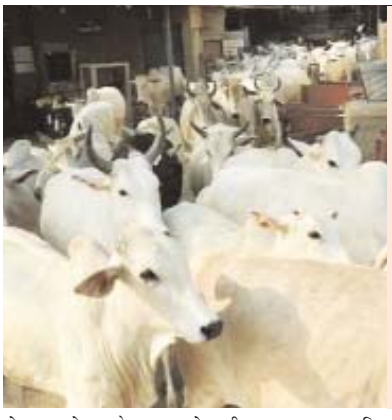

यह रहे मौजूद

बैठक में बोर्ड की कार्यपरिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि प्रबंध संचालक एवं संचालक पशुपालन डॉ. आर के मेहिया, मप्र राज्य कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक डॉ. एचबीएस. भदौरिया, ग्रामीण विकास विभाग के ज्वाईट कमीश्नर एमएल त्यागी मौजूद थे।

-नर्मदांचल में महिला किसान ने उगाई आंध्रप्रदेश की किस्म

हल्दी की खेती, आठ माह में चार लाख रु.का फायदा

2020 में पीएम ने कृषि कर्मण अवॉर्ड से किया था सम्मानित

नर्मदापुरम। जागत गांव हमार

नर्मदांचल की धरती पर आंध्रप्रदेश की सुरोमा किस्म की हल्दी की खेती कर महिला किसान लाखों रुपए की कमाई कर रही हैं। साथ ही, 10 लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। अब अन्य किसान भी हल्दी की खेती के लिए प्रेरित हो रहे हैं। उद्यानिकी विभाग भी पहली बार नर्मदापुरम में हल्दी की खेती को बढ़ावा दे रहा है। जिले में अब करीब 100 हेक्टेयर में हल्दी की बोवनी की गई है। दरअसल, नर्मदापुरम जिले के ग्राम सोमलवाड़ा की महिला किसान कंचन शरद वर्मा ने बीए होम साइंस की पढ़ाई की है। उनके पति शरद वर्मा उन्नत किसान हैं। जैविक अनाज, फल के उत्पादन में परिवार की अलग पहचान है। कंचन वर्मा ने एक एकड़ में 40 क्विंटल गेहूं की पैदावार कर 2020 में कृषि कर्मण अवॉर्ड जीता था। बेंगलुरु के तुमकुर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अवॉर्ड प्रदान कर सम्मानित किया था।

मुनाफा 1.10 लाख- नर्मदापुरम से 25 किमी दूर ग्राम सोमलवाड़ा में किसान कंचन शरद वर्मा ने हल्दी की खेती के बारे में बताया कि 3 साल पहले हल्दी की खेती शुरू की थी। पहले साल एक एकड़ में फसल लगाई। जिसमें पक्की हल्दी 16 क्विंटल हुई। मुनाफा 1.10 लाख हुआ। दूसरे साल 4 एकड़ में हल्दी लगाई। इस बार उद्यानिकी विभाग से आंध्रप्रदेश में मिलने वाली प्रसिद्ध सुरोमा (किस्म) की हल्दी लगाई। जिसमें प्रति एकड़ 100 क्विंटल गीली हल्दी की पैदावार हुई। जो सूख कर 17 क्विंटल प्रति एकड़ हुई। इस साल 6 एकड़ में हल्दी लगाई है।

मंडी जाने की जरूरत नहीं-कंचन ने बताया कि हल्दी की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि हमें इसे बेचने के लिए ज्यादा प्रचार-प्रसार या मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहां आसपास के गांव और शहरों से लोग हल्दी लेने आते हैं। घर से ही पूरी हल्दी बिक जाती है। अधिकांश व्यापारी थोक में खरीदकर ले जाते हैं। कंचन, उनके पति शरद वर्मा और परिवार सोमलवाड़ा गांव से दूर खेत में ही रहता है। उनका फार्म हाउस भी है। वे क्षेत्र के उन्नत और जैविक खेती के क्षेत्र में बड़े किसान है। सैकड़ों एकड़ खेती में अनाज का उत्पादन करते हैं। घर के आसपास अमरूद, कटहल, बैंगन, भिंडी समेत अन्य फल-सब्जियों के भी बगीचे लगाए हैं।

जिले की मिट्टी उपयुक्त

किसान कंचन की मेहनत के बाद हल्दी में हुए मुनाफे को देखकर उद्यानिकी विभाग ने भी नर्मदापुरम जिले में हल्दी की फसल को बढ़ावा दिया। उद्यानिकी विभाग की उप संचालक रीता उईके ने बताया कि जिले की मिट्टी हल्दी की खेती के लिए उपयुक्त है। यहां की जलवायु हल्दी की खेती के लिए अनुकूल है। पहली बार जिले में करीब 100 हेक्टेयर के रकबे में हल्दी की बोवनी की गई है। सिवनी मालवा, पिपरिया आदि क्षेत्रों में किसानों को हल्दी की फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। किसान इसे अपना रहे हैं। पिछले दो-तीन साल से बोवनी करने वालों की संख्या बढ़ी है, इसलिए हल्दी के बीज पर विभाग की तरफ से किसानों को 40 फीसदी तक सब्सिडी भी दी जा रही है। एक एकड़ में करीब 8 क्विंटल बीज लगता है।

एक एकड़ में 1.20 लाख मुनाफा | कंचन के अनुसार उन्होंने पहले साल एक एकड़ में हल्दी की बोवनी की। 100 क्विंटल गीली हल्दी से 17 क्विंटल पक कर हल्दी तैयार हुई। एक एकड़ में लागत 50-60 हजार रुपए आई। 17 क्विंटल हल्दी बेचने पर 1.70 लाख रुपए मिले। यानी 1.20 लाख की आय हुई। 4 एकड़ में साढ़े 4 लाख की आय हुई। इस बार फिर 6 एकड़ में हल्दी लगाई है। पौधे में निढ़ाई चल रही है।

कब करनी चाहिए खेती | हल्दी की फसल 8 से 9 महीने में तैयार होती है। मई, जून में खेत तैयार कर इसकी बोवनी कर सकते हैं। एक एकड़ में करीब 8 क्विंटल बीज लगा सकते हैं। इसकी लागत 60 से 70 हजार रुपए प्रति एकड़ आती है। जिससे एक से डेढ़ लाख रुपए की आय प्रति एकड़ प्राप्त हो सकती है। एक एकड़ में करीब एक क्विंटल बीज लगता है। जिसमें करीब 100 क्विंटल गीली हल्दी का उत्पादन होता है।

गहरी जुताई की जरूरत | किसान शरद वर्मा ने बताया कि हल्दी की बोवनी से पहले खेत की गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। 3 ट्रॉली प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद डालें। इसके बाद 9-9 इंच की दूरी के अंतर से बीज रोपे। जिसमें प्लांट-टू-प्लांट 8-9 इंच और रो-टू-रो 3 फीट का अंतर हो। इसमें कीड़े या फंगस रोग लगने की चिंता नहीं रहती। अलग-अलग वैराइटी के हिसाब से ये कम ज्यादा हो सकता है। बीज की बुआई के समय ध्यान रखना चाहिए कि बीज अच्छी वैराइटी का हो और कम से कम 7 सेमी लंबा हो। हर 20-25 दिन की अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। मौसम ठंडा है या नमी वाली जगह पर आपने खेती की है तो फिर सिंचाई की जरूरत कम होगी।

हल्दी की वैराइटी

हल्दी की कई वैराइटी होती है। किसी का कलर अलग होता है, तो किसी का साइज कम-ज्यादा होता है। वैराइटी के आधार पर प्रोडक्शन और क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है। **आइए कुछ प्रमुख वैराइटी को जानते हैं...**

- **सुगंधमः** हल्दी की ये किस्म 200 से 210 दिन में तैयार हो जाती है। इसका आकार थोड़ा लंबा होता है और रंग हल्का पीला होता है। प्रति एकड़ 80 से 90 क्विंटल का प्रोडक्शन होता है।
- **पीतांबरः** हल्दी की इस वैराइटी को ने डेवलप किया है। यह बाकी हल्दी की तुलना में पहले तैयार हो जाती है। यानी 5-6 महीने का वक्त लगाता है। एक एकड़ में 270 क्विंटल तक उपज होती है।
- **सुदर्शनः** हल्दी की ये वैराइटी आकार में छोटी होती है, लेकिन दिखने में खूबसूरत होती है। 230 दिन में फसल पक कर तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ 110 से 115 क्विंटल की पैदावार होती है।
- **सोरमाः** इसका रंग सबसे अलग होता है। हल्के नारंगी रंग वाली हल्दी की ये फसल 210 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ प्रोडक्शन 80 से 90 क्विंटल होता है।

पति हरे चारे से बने करोड़पति

कंचन वर्मा के पति शरद वर्मा जिले और एमपी के स्मार्ट किसान भी है। शरद हरा चार सही उपयोग कर करोड़पति बन गए है। शरद ने न्यूजीलैंड से हरा चारा साइलेज बनाने की विधि और तकनीक जानी। रिसर्च कर अपने गांव में खेती शुरू की और अब वो करोड़पति किसान बन गए हैं। उनके देखा देखी आसपास के किसान भी यही खेती करने लगे हैं। किसान शरद वर्मा ने साइलेज हरे चारे की खेती 10 एकड़ से शुरू की थी। उन्हें इतना फायदा हुआ कि अब 100 एकड़ में हरे चारे साइलेज की खेती कर रहे हैं। वह मप्र में इकलौते किसान है जो इतने बड़े रकबे में खेती कर यूनिट से साइलेज तैयार कर रहे हैं। जो मध्यप्रदेश में जबलपुर, भोपाल, बैतूल, मुलताई, हरदा, नर्मदापुरम सहित इटारसी की बड़ी-बड़ी डेयरी और पशुओं की नर्सरी में सप्लाई हो रही है। वे 75 से 80 दिन में 50 लाख रुपए का मुनाफा कमाते हैं।

वन मंत्री विजय शाह ने कहा-वनोपज के माध्यम से गरीब कल्याण की अनेक संभावनाएं

महुआ संग्राहकों को अच्छा दाम दिलाने का प्रयास करेगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

वन मंत्री विजय शाह ने प्रशासन अकादमी में राष्ट्रीय महुआ कानक्लेव आयोजन के अवसर पर कहा कि वनोपज के माध्यम से गरीब कल्याण की दिशा में व्यापक संभावनाएं हैं। प्रदेश में महुआ संग्राहकों को बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। महुआ संग्रहण के लिए इन परिवारों को नि:शुल्क जाल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उत्तम गुणवत्ता का महुआ संग्रहित किया जा सके।

वन मंत्री ने महुआ के सामाजिक सशक्तिकरण एवं आर्थिक उन्नयन पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि मध्यप्रदेश का महुआ संग्रहण में अग्रणी स्थान है। अभी तक महुआ वनोपज का सीमित उपयोग होता था, इसी प्रकार वनवासियों को महुआ वनोपज का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता था। राज्य शासन द्वारा की गई पहल से संग्राहकों को अब महुआ संग्रहण का अच्छा मूल्य प्राप्त हो पा रहा है। इसके लिए वनवासियों को महुआ पेड़ के नीचे जाल बिछाकर महुआ संग्रहण के लिए जागरूक किया

गया है। वन मेले के माध्यम से महुआ विपणन में अब बेहतर कीमत मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब विभागीय रोपणों में 50 प्रतिशत वनोपज प्रजाति के पौधों के रोपण का निर्णय लिया गया है। इससे भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में इमारती लकड़ी के साथ-साथ लघु वनोपज भी प्राप्त हो सकेगी। हाईटेक टिशुकल्चर नर्सरी में महुए के पौधों को तैयार किए जाएंगे।

वनमंत्री ने इस अवसर पर मप्र में लघुवनोपज की उत्पादन क्षमता का आंकलन प्रतिवेदन का विमोचन किया। वनमेला-2022 की चित्रमयी प्रस्तुति का दस्तावेज जारी किया। एमएफपी पार्क के हर्बेरियम डाटाबेस को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य न्यूयार्क बॉटनिकल गार्डन की वेबसाइट इडेक्स हर्बेरियम डाटाबेस सिस्टम वेबसाईट का लोकार्पण किया। उन्होंने वन-धन नैचुरल्स की नवीन पैकेजिंग का लोकार्पण किया। वनमंत्री द्वारा प्रदेश में फुडग्रेड महुआ संग्रहण में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आठ जिला वनोपज सहकारी यूनियनों का सम्मान किया।

आजीविका से महुआ जुड़ा हुआ

अपर मुख्य सचिव वन जेएन कांसोटिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका से महुआ जुड़ा हुआ है। इसके विकास तथा विपणन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। प्रधान मुख्य संरक्षक एवं वनबल प्रमुख रमेश कुमार गुप्ता ने कहा कि महुए की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में विगत कुछ वर्षों में किए गये प्रयासों के परिणाम मिलना शुरू हो गए हैं। प्रबंध संचालक मप्र राज्य वनोपज संघ पुष्कर सिंह ने कहा कि महुए पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे प्रयासों से भविष्य में महुआ संग्रहणकर्ताओं को लाभ प्राप्त होगा। वरिष्ठ वन अधिकारी, विषय विशेषज्ञ एवं महुआ संग्राहक उपस्थित थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमएफपी पार्क डॉ. दिलीप कुमार ने समापन अवसर पर महुआ कानक्लेव डिक्लेरेशन के माध्यम से इस एक दिवसीय आयोजन के तीन सत्रों के दौरान विषय विशेषज्ञों द्वारा की गई चर्चा के आधार पर महुआ पर भविष्य की रणनीति प्रस्तुत की। राष्ट्रीय महुआ कानक्लेव में लंदन से श्री अनिल पटेल, पेरिस से राहुल श्रीवास्तव ने अपने अनुभव बताए। पटेल ने बताया कि मध्यप्रदेश से निर्यातित महुआ के द्वारा उन्होंने अनेक उत्पाद तैयार किये हैं, जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मांग है।

भारत के 'असली अन्नदाता' एमएस स्वामीनाथन का निधन

एक ऐसा सख्श जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता, लेकिन बंगाल के अकाल ने उनकी दिशा ही बदल कर रख दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पढ़े-लिखे स्वामीनाथन को असल मायने में भारत का अन्नदाता कहा जा सकता है। उनकी मदद से धान और दूसरी फसलों में भी कृषि क्रांति के बीज रोपे गए। उन्हें 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1989 में स्वामीनाथन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्होंने इतने बड़े देश को भुखमरी से बाहर निकालने में मदद की। 1971 में, उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। उन्होंने दुनिया का पहला वर्ल्ड फूड प्राइस हासिल किया।

भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले कृषिवैज्ञानिक प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया है। आजादी के बाद अनाज की भारी कमी से जूझ रहे भारत में 1960 के दशक में स्वामीनाथन के नेतृत्व में ही हरित क्रांति लाई गई।

स्वामीनाथन का गुरुवार 28 सितंबर को चेन्नई स्थित उनके निवास पर निधन हो गया। वो 98 बरस के थे। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिसके तहत अपनाई गई नीतियों की बदौलत भारत अनाज की भारी कमी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा।

उन्होंने ज्यादा पैदावार देने वाली धान और गेहूं की किस्मों के आविष्कार में अग्रणी भूमिका अदा की जिसकी वजह से भारत के किसान 1960 के दशक के बाद से अपनी पैदावार बढ़ाने में सफल हो पाए।

हरित क्रांति के जनक: 1950 के दशक में भारतीय कृषिशोध संस्थान (आईएआरआई) में काम करते समय वो ज्यादा पैदावार देने वाली गेहूं की फसलों पर शोध कर रहे थे। उस दौरान उन्हें अमेरिकी कृषिवैज्ञानिक नार्मन बोरलॉग के बारे में पता चला, जो उस समय अमेरिका के रॉकफेलर संस्थान के मेक्सिको कृषिकार्यक्रम के लिए काम कर रहे थे।

मेक्सिको में वो ज्यादा पैदावार देने वाली गेहूं की किस्में विकसित कर रहे थे। स्वामीनाथन के कहने पर भारत सरकार ने बोरलॉग को भारत आने का निमंत्रण दिया। गेहूं उगाने वाले कुछ राज्यों का मुआयना करने के बाद उन्होंने मेक्सिकन किस्मों के 100 किलो बीज भारत को दिए। कुछ समय के ट्रायल के बाद इन बीजों को सबसे पहले दिल्ली में बोया गया और पाया गया कि पैदावार काफी बढ़ गई थी। पौधे पहले एक से डेढ़ टन प्रति हेक्टेयर की जगह अब चार से साढ़े चार टन प्रति हेक्टेयर गेहूं देने लगे।

1965-66 और 1966-67 में भारत में दो साल लगातार सूखा पड़ा। अनाज का उत्पादन गिर गया और भारत को अमेरिका से आयात पर निर्भर होना पड़ा। स्वामीनाथन के प्रयास इसी समय में भारत के काम आये और उनकी देखरेख में ज्यादा पैदावार वाली नस्लें उगाई गईं।

इनसे भारत में अनाज का उत्पादन बढ़ गया और भारत अनाज के संकट से बाहर निकल गया। भारत की हरित क्रांति के पीछे और भी लोगों का हाथ था, लेकिन जानकारों का मानना है कि स्वामीनाथन की भूमिका केंद्रीय थी। हरित क्रांति के कई तरह के बुरे असर भी चर्चा में रहते हैं लेकिन अनाज संकट से देश को उबारने की उपलब्धि को किसी ने नकारा नहीं है।

किसानों के हितैषी

स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के इतिहास के संकट के एक काल में कृषिक्षेत्र में स्वामीनाथन के काम ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया और देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की।

कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी भारत को अनाज में आत्मनिर्भर बनाने की उनकी उपलब्धि के लिए उन्हें नमन किया। हरित क्रांति के अलावा स्वामीनाथन को और भी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है।

2004 में भारत में किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बीच कृषिक्षेत्र में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष स्वामीनाथन को ही बनाया गया था। आयोग ने लंबे शोध के बाद सुधार के कई कदम सुझाए जिन्हें ऐतिहासिक माना जाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए इस आयोग ने जो फार्मूला दिया वो स्वामीनाथन फार्मूला नाम से मशहूर है। इसके तहत आयोग ने सुझाया था कि किसी फसल पर एमएसपी, उसकी लागत के औसत खर्च से कम से कम 50 प्रतिशत ज्यादा होनी चाहिए।

किसान कल्याण की राह में इसे मील का पत्थर माना जाता है, लेकिन सरकारें आज तक इस फॉर्मूले को लागू नहीं कर पाईं। स्वामीनाथन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। वो राज्य सभा के सदस्य भी रहे। उन्हें 1987 में कृषिक्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला पहला वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च संस्थान की स्थापना की।

संस्थान तब से कृषि क्षेत्र में शोध के कार्यों में लगा हुआ है। स्वामीनाथन की बेटी और विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन संस्थान की मौजूदा अध्यक्ष हैं।

मुर्गियों में कोक्सीडियोसिस रोग और बचाव के उपाय

» डॉ. याशिर आमीन राथेर
» डॉ. शानू देवी सिंगौर
» डॉ. शाहबाज़ हारुन खान्
» डॉ. ब्रजमोहन सिंह धाकड
» डॉ. रीना डोडव्
» डॉ. हर्षिता पेंडाम
» डॉ. सिध्दी वेल्हाल
-कुक्कुट विज्ञान विभाग, पशुचिकत्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, नादेपविवि जबलपुर मप्र।
-पशुचिकत्सा जनस्वास्थय और महमारी विज्ञान विभाग, पशुचिकत्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, नादेपविवि जबलपुर, मप्र।

कोक्सीडियोसिस बारिश के मौसम में होने वाला मुर्गीयों में एक जानलेवा रोग है। ये रोग एक प्रोटोजोओन परजीवी आइमेरिया के विभिन्न प्रजातियों के संक्रमण के कारण होता है। आइमेरिया के विभिन्न प्रजातियों में आइमेरिया टेनैला, आइमेरिया नेकाट्रिक्स, आइमेरिया ऐसिरभुलिना, आइमेरिया मैक्सिमा, आइमेरिया माइटिस, आइमेरिया प्रीकॉक्स तथा आइमेरिया ब्रुनेटाई प्रमुख हैं। ये परजीवी आँतों के कोशिकाओं को छेद कर उन्हें बुरी तरह क्षति ग्रस्त कर देते हैं, जिसके कारण मुर्गीयों में दस्त तथा खूनी अतिसार जैसे लक्षण होने लगते हैं। जिसके कारण मुर्गीयों के शरीर मे पानी कि कमी होती हैं।

कोक्सीडियोसिस रोग के कारण मुर्गी पोषक तत्वों का अवशोषण कर नहीं पाती हैं, फलस्वरूप उनमें वजन की कमी और मृत्युदर की अधिकता होती है। ये रोग हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी भारी क्षति पहुँचाते है। क्योंकि इस रोग में मुर्गियों की उत्पादन क्षमता तथा विकास की दर घट जाती है।

कैसे फैलता है रोग: कोक्सीडियोसिस संक्रमित मुर्गी परजीवी के ऊशिष्ट (युग्मक-पुटी) का उत्सर्जन अपने मल द्वारा करती हैं। इन युग्मक- पुट्टीओं का शरीर के बाहर बीजाणुक जनन (स्पोरुलेशन) होता है। जब ये बीजाणुक जनक युग्मक पुट्टीयों को कोई स्वस्थ मुर्गी जल या खाद्य पदार्थों द्वारा निगल लेती है, तो उस मुर्गी में भी इस रोग का संचरण होता है। युग्मक पुट्टीयों का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण आगंतुकों के जूते, खाद्य पदार्थ,पालतु पशुओं, कतरने वाले जीव तथा चलत उपकरणों द्वारा भी होता है। ये युग्मक पुट्टीया कुड़ा-करकटों में महीनों तक जीवित रहते हैं इस तरह वे साल भर किसी भी मुर्गी प्रक्षेत्र को संक्रमित कर सकते हैं।

प्रमुख कारक जो संक्रमण के प्रबलता को प्रभावित करते हैं- मुर्गियों द्वारा निगले गये युग्मक पुट्टियों की संख्या-यदि बहुतायत संख्या में युग्मक पुट्टियों को खाया गया है तो संक्रमण की प्रबलता भी अधिक होगी।

संक्रमण की तीव्रता कोक्सीडिया परजीवीयों के विभिन्न नस्लों पर भी निर्भर करती है। कुछ नस्ल के कॉक्सीडिया परजीवियों की रोग तीव्रता अधिक होती है।

पक्षियों की उम्र: कम उम्र के मुर्गियां, वयस्क मुर्गियों अपेक्षा में रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

पोषण अवस्था: कुपोषित या अल्पपोषित मुर्गी इस रोग से ज्यादा प्रभावित होती हैं।

कोक्सीडियोसिस रोग के प्रकार

मुर्गियों में कोक्सीडियोसिस दो प्रकार के होते हैं।

1. आँत्रीय कॉक्सीडियोसिस
2. अन्धांत्रा काक्सीडियोसिस

1. आँत्रीय कॉक्सीडियोसिस आइमेरिया नेकाट्रिक्स, आइमेरिया एसिरेभुलिना तथा आइमेरिया मैक्सिमा के कारण होता है। आइमेरिया नेकाट्रिक्स द्वारा जनित आंत्रीय कॉक्सीडियोसिस सबसे प्रबल एवं जानलेवा होता है। आइमेरिया ऐसेरभुलिना तथा आइमेरिया मैक्सिमा छोटी आंतों के उपकला कोशिकाओं में विकसित होते हैं और दीर्घकालीन आंत्रीय कॉक्सीडियोसिस रोग के कारक होते हैं।

2. अंधात्रा कॉक्सीडियोसिस आइमेरिया टैनेला प्रजाति के कारण होता हैं और ये मुख्यत: अल्पव्यस्क मुर्गियों को प्रभावित करता हैं। ये कॉक्सीडियोसिस आंत्रीय कॉक्सीडियोसिस से भी अधिक घातक होता है और मुर्गियों की मृत्युदर की अधिकता भी इसी कॉक्सीडियोसिस के कारण होती है। जिसके कारण कुक्कुट उद्योगों को भारी क्षति पहुंचती है। इन दोनों कॉक्सीडियोसिस के अतिरिक्त गुदा संबंधी कॉक्सीडियोसिस भी मुर्गियों में सामान्य है जो मुख्यत: आइमेरिया ब्रुनेटाई के संक्रमण के कारण होता है।

कॉक्सीडियोसिस रोग के लक्षण: अतिसार, दस्त, मल में खून आना, वजन में कमी, भूख न लगना, निर्जलीकरण, रोग की पहचान रोग के लक्षण देखकर, मल का सूक्ष्मदर्शी द्वारा जाँच कर पंचनामा में को देखकर, उपचार।

कॉक्सीडियोसिस के उपचार के लिए बहुत सारे दवाईयाँ बाजार में उपलब्ध हैं इनमें से प्रमुख दवाईयाँ तथा उनका खुराक निम्नलिखित है।

सल्फा क्युनॉक्सालीन 100 ग्राम प्रति 50 किलो खाद्य पदार्थ के साथ या 10 ग्राम 10 लीटर पीने के पानी में मिलाकर। सल्फाडाइमिडिन 10 ग्राम प्रति 20 लीटर पेय जल में मिलाकर। एम्प्रोलियम 30 ग्राम प्रति 30 लीटर पेय जल मे मिलाकर अन्य सल्फा दवाओं के संयोजन के साथ। मोनिन्सीन 50-60 ग्राम प्रति 100 किलो खाद्य पदार्थों के साथ। सालिनोमाइसिन 30-50 ग्राम प्रति 100 किलो खाद्य पदार्थों के साथ।

नियंत्रण के उपाय: (क) कॉकसिडियोसिस प्रभावित मुर्गियों को रसायिनक दवाओं द्वारा नियंत्रण करें। **(ख)** पानी तथा खाने के पात्रों को थोड़ा ऊँचाई पर रखना चाहिए ताकि मुर्गी उसमें मल त्याग न कर सकें। **(ग)** मुर्गियों को ज्यादा आटा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन में पाया है कि ज्यादा आटा खाने वाली मुर्गीया इस रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। **(घ)** मुर्गियों के कुड़ा करकटों को नियमित बदलते रहना चाहिए तथा मुर्गियों को प्रत्येक समय-समय पर रोगाणुमुक्त करना चाहिए। **(ड़)** कुड़े को सुखा रखना चाहिए ताकि उसमें युग्मक पुट्टियों का विजनुक जनन न हो पाये। **(च)** मुर्गी प्रलेग की भीड़ से बचाना चाहिए। **(छ)** स्वच्छ पेयजल तथा खाद्य पदार्थ रखे। **(ज)** टीकाकरण के द्वारा- आजकल बाजार में कॉक्सीडियोसिस रोग के लिए अनेको टीका उपलब्ध है जिनको सही समय पर लगाकर इस रोग की रोकथाम की जा सकता है इन टीकाओं में कॉक्सीक, पाराकॉक्स, लिवाकॉक्स प्रमुख है।

आने वाले समय में हो सकती है पानी की किल्लत, अभी से जागरूक होना जरूरी

इस बार गर्मी ने जो रंग दिखाया उससे वास्तव में सभी के चेहरे के रंग उड़ गए। सूर्य की तपिश में मानों हर जीव झुलस रहे हों। नदियों का पानी सूखने की कगार पर आ गया। यहां तक कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल सूख गए, पोखर, तलाब सूख गए। कुंआ का अस्तित्व तो विलुप्त ही है। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां कभी पानी की किल्लत होती ही नहीं थी। इस बार वो भी क्षेत्र बिन पानी सून है। सूर्य की तपिश ऐसी की मानों जला ही दें और हुआ भी यही की इसबार हीटवेव के कारण कितनों की जानें चली गई। अधिकांश जगहों पर तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस रहा है। ये सामान्य सी घटना नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचने का विषय है। आने वाले 10 साल में स्थिति ऐसी ही रही तो ये कहना गलत नहीं होगा की आसमान से आग बरसेगी और ये सिलसिला बढ़ता ही रहा तो आने वाले 40-50 साल में पूरा देश पानी की समस्या से जूझ रहा होगा और तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका होगा। तब की स्थिति की कल्पना ही भयभीत करती है।

हम पर्यावरण संरक्षण को भूलते जा रहे: आने वाले समय में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगे ऐसा मुमकिन नहीं लगता। नदियां प्रदूषण मुक्त हो जाएगी ऐसी बातें करना ही मूर्खतापूर्ण है। हम भौतिक सुखों में प्रकृति को भूलते जा रहे है। पर्यावरण संरक्षण की बातें बस पर्यावरण दिवस पर ही सुनने को मिलती है। सच्चाई तो ये है कि हमारे पास इन विषयों पर सोचने के लिए समय ही नहीं है। कम से कम आने वाले वक्त के लिए तो अभी से कमर कस ही लेनी चाहिए कि अन्न-जल के अभाव में मरना है। अगर हम बच भी गए तो आने वाली पीढ़ी इसका दंश झेलेगी ही झेलेगी। साल 2018 में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन में 122 देशों के जल संकट की सूची में भारत रहा है। 2070 तक भारत की आधी आबादी सूर्य की तपिश और पानी के अभाव में अपना जीवन यापन कर रहा होगा।

वैज्ञानिकों की चेतावनी कुछ दशक बाद पानी की होगी किल्लत: कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ती आबादी की जरूरतों और सिंचाई के लिए भारी मात्रा में जमीन से पानी निकाला जा रहा है। इससे पृथ्वी की धुरी प्रभावित हुई है। साथ ही इसके घूमने का संतुलन भी बिगड़ा है। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के भू- भौतिकीविद डॉ। की वेन सीओ ने बताया है कि पृथ्वी की धुरी में बदलाव और भूजल दोहन के बीच मजबूत संबंध सामने आना। वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़ा आश्चर्य है। जल विशेषज्ञों ने लंबे समय से भूजल के अत्यधिक उपयोग के परिणामों के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूजल तेजी से महत्वपूर्ण संसाधन बनता जा रहा है। दरअसल जमीन से पानी तो निकाला जा रहा है, लेकिन इसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। इससे जमीन अपने स्थान से खिसक सकती हैं, जिससे घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। हमारी बड़ी लापरवाही से भूजल के स्रोत हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। अब जरूरी है पर्यावरण के लिए जागरुक होना। अब समय आ चुका है कि हम सभी पर्यावरण के प्रति जितना सतर्क हो जाएं, उतना बेहतर। साथ ही साथ पर्यावरण के लिए लोगों को भी जागरुक होना पड़ेगा।

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया भूमि-पूजन

25 करोड़ की लागत से भदभदा में बनेगा एक्वा पार्क-अनुसंधान केंद्र

भोपाल। जागत गांव हमार

जल-संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार मत्स्य-पालकों के कल्याण के लिये कटिबद्ध, वचनबद्ध और प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश मत्स्य-पालन में अग्रणी है और मछुआरों के क्रेडिट-कार्ड बनाने में देश में प्रथम है। प्रदेश का बालाघाट जिला मत्स्य-उत्पादन में देश में प्रथम है। मछुओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना बनाई है और योजना का सफल क्रियान्वयन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में किया जा रहा है। मंत्री ने भदभदा मत्स्य प्रक्षेत्र भोपाल में 25 करोड़ की लागत से लगभग 4 एकड़ भूमि पर बनने वाले एक्वा पार्क एवं अनुसंधान केंद्र का भूमिपूजन किया। केन्द्र के वित्तीय सहयोग से जलीय जीवों के प्रदर्शन, उनके जीवन अध्ययन और इससे संबंधित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है।

मंत्री ने निर्देश दिए कि पार्क का निर्माण तय समय-सीमा में उच्च गुणवत्तापूर्ण कराया जाए। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मछुओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। केवट समाज का देश के विकास में सराहनीय योगदान रहा है। उनके कार्यों से हमें नई ऊर्जा और शक्ति मिलती है। वे केवट ही थे, जिन्होंने भगवान श्रीराम, लक्ष्मण एवं जानकी को गंगा पार कराया था।

भोपाल में मत्स्य-पालकों के लिए 7 करोड़ की लागत से भवन बनाया जाएगा

मंत्री सिलावट ने बताया कि मत्स्य-पालकों को रुकने और भोजन के लिए भोपाल सहित सभी जिलों में भवन बनाए जाने की योजना है। उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि से गांधी सागर तथा जिन अन्य क्षेत्रों में मछुआरों को नुकसान हुआ है, उसका सर्वे कराकर यथासंभव सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम बाथम ने बताया कि भोपाल में मत्स्य-पालकों के लिए 7 करोड़ की लागत से भवन बनाया जाएगा। मंत्री ने शिला-पट्टिका का अनावरण और द्वीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक नारायण पटेल, प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव, अपर सचिव अनुराग चौधरी, प्रबंध संचालक पुरुषोत्तम दीवान, संचालक भरत सिंह तथा बड़ी संख्या में मत्स्य-पालक मौजूद थे।

कम समय में मटर की उन्नत किस्मों की खेती किसानों के लिए फायदमंद

भोपाल। जागत गांव हमार

देश के कई राज्यों में मटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मटर का उपयोग सब्जी के साथ-साथ दलहन के रूप में भी किया जाता है। अगेती मटर की खेती कम समय में अच्छा मुनाफा देती है जिसके चलते इसकी मांग बढ़ रही है। मटर एक दलहनी फसल है जिसकी खेती देश में अगेती और पिछेती किस्मों के आधार पर की जाती है। अगेती मटर की किस्म की बोवनी के लिए सितंबर माह के अंत से अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े तक की जाती है। वहीं पिछेती मटर की बोवनी नवंबर के अंत तक की जा सकती है। मटर की खेती के लिए दोमट और हल्की दोमट मृदा दोनों ही उपयुक्त होती है। किसान मटर की उन्नत प्रजातिओं की बोवनी सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के मध्य तक कर सकते हैं। मटर की इन किस्मों की सबसे खास बात यह है कि ये सभी 50 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है। जिससे खेत जल्दी खाली हो जाता है और किसान दूसरी फसलों की बोवनी इसके बाद कर सकते हैं।

अगेती मटर की उन्नत किस्में

देश के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा भारत की अलग-अलग जलवायु के अनुसार अलग-अलग कस्में विकसित की है। यह किस्में अधिक पैदावार के साथ ही रोग रोधी भी होती हैं जिससे फसल की लागत में भी कम आती है। अगेती मटर की उपयुक्त किस्में आजाद मटर, काशी नंदिनी, काशी मुक्ति, काशी उदय, काशी अगेती, पूसा प्रगति, पूसा श्री, पंत मटर-3, अर्किल आदि शामिल है। किसान अपने क्षेत्र के अनुसार उपलब्ध मटर की इन किस्मों में से किसी का चयन कर बोवनी कर सकते हैं।

मटर की बोवनी के लिए क्या करें

बोवनी के लिए प्रति हेक्टेयर 80 से लेकर 100 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। मटर को बीजजनित रोगों से बचाव के लिए मैंकोजेब 3 ग्राम या थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। अगेती प्रजातिओं के लिए पंक्ति से पंक्ति एवं पौधे से पौधे की दूरी 30*6-8 सेंटीमीटर पर्याप्त है। खेत की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 20-25 टन सड़ी गोबर की खाद के साथ 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश का उपयोग करना चाहिए।

मध्य प्रदेश के सात उत्पादों को मिला जीआई प्रमाण पत्र

भोपाल: नाबार्ड, मप्र क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गत दिवस जीआई कार्यशाला का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि नाबार्ड, संत रविदास मप्र हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, तथा जनजातीय कल्याण विभाग के सम्मिलित प्रयासों एवं ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से मप्र के 7 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कार्यशाला में 7 जीआई टैग उत्पादों जैसे ग्वालियर हैंडमेड कार्पेट, जबलपुर स्टोन क्राफ्ट, सुंदरजा आम, शरबती गेहूं, बाटिक प्रिंट, गोंड चित्रकारी एवं वारासिवनी हैंडलूम साड़ी के रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर एवं फैसिलिटेटर उपस्थित थे। इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा जीआई टैग के रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर एवं फैसिलिटेटर को जीआई प्रमाण पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम के दौरान सुनील कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, मप्र क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड ने पंजीकृत संस्थाओं को जीआई प्राप्त करने के लिए बधाई दी गई। जीआई टैग के उपयोग से किस प्रकार आमदनी की वृद्धि एवं उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय पर प्रकाश डाला गया। श्री कुमार ने सभी संस्थाओं को प्रेरित किया तथा जीआई टैग का अधिकतम उपयोग कर उत्पादों को राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने की अपील की।

कार्यशाला में ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के डॉ. रजनीकांत द्विवेदी, पद्मश्री से सम्मानित, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत के स्वदेशी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सराहा जाएगा, जो कि वास्तव में उनके प्रयासों को सफल बनाएगा। कार्यशाला के अवसर पर मुख्य आकर्षण जीआई पवेलियन रहा जिसे उपस्थित प्रतिभागियों ने खूब सराहा, इस पवेलियन में सातों जीआई पंजीकृत उत्पाद प्रदर्शित किए गए।

विश्व की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना के लिए 217.14 करोड़ का ऋण अनुबंध

कुसुम-सी परियोजना के 7 विकासकों को 82.9 मेगावॉट के सेटर आफ अवॉर्ड

भोपाल। जागत गांव हमार

विश्व के सबसे बडे ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट में विद्युत ग्रिड संयोजन के लिए आवश्यक सब स्टेशन निर्माण के लिए आरईसी लिमिटेड और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के मध्य 217 करोड़ 14 लाख रुपए का ऋण अनुबंध निष्पादित किया गया। अध्यक्ष गिर्राज दंडोतिया और प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम कर्मवीर शर्मा की उपस्थिति में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड की ओर से परियोजना प्रभारी अवनीश शुक्ला और आरईसी की ओर से प्रदीप ने हस्ताक्षर किए। यह ऋण स्वदेशी संस्थान से होने के कारण आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी प्राप्त कराने में सहायक होगा। रीवा अल्ट्रा मेगा कंपनी द्वारा प्रदेश में अब तक एक हजार मेगावॉट के सौर पार्क और परियोजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही हैं।

ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिर्राज दण्डोतिया ने आज कुसुम-सी परियोजना में 82.9 मेगावॉट की 14 परियोजनाओं के 7 विकासकों को लेटर ऑफ अवार्ड का वितरण किया। किसानों को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित कुसुम-सी परियोजना में रायसेन जिले की 26 मेगावॉट की 4 परियोजनाओं के लिए पुरुषोत्तम प्रो. प्रा.लि. को, शाजापुर जिले की 14.4 मेगावॉट की 2 परियोजना के लिए भैरव एम्ब्रो डिजाइन, 14.6 मेगावॉट की 3 परियाजना के लिए रिनी पॉवर 6.3 मेगावॉट की 2 परियाजना के लिए सचिन बंसल कान्ट्रेक्टर, 8 मेगावॉट की एक परियोजना के लिए रिद्धि-सिद्धि इलेक्ट्रीकल इंजीनियर और 5.7 मेगावॉट की एक परियाजना एसके इलेक्ट्रीकल्स तथा बुरहानपुर जिले 7.9 मेगावॉट की झम्ब ट्रेडिंग कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड दिया गया।

जिले के कई गांवों में धान की फसल में लट का प्रकोप, चिंतित हुए किसान

लट कर रही धान को चट, कीटनाशक दवाए भी बेअसर

श्योपुर। जागत गांव हमार

पानी की कमी के बीच खेतों में लहलहा रही धान की फसल पर लट का प्रकोप देखा जा रहा है। यह लट धान के पौधों की वाली को चट कर रही है। इससे धान के पौधों का वाली वाला हिस्सा सूखता जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी इस रोग का नाम स्टेम बोरर बता रहे है। धान की फसल में इस रोग का प्रकोप जिले में कई जगह देखा जा रहा है,लेकिन सबसे ज्यादा प्रकोप सोंईकलां, बडौदा और राडेप क्षेत्र में देखा जा रहा है। हालांकि किसान इस रोग से धान को बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे है, मगर कीटनाशक दवाएं भी बेअसर साबित हो रही है। जिसके चलते किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन कृषि विभाग का मैदानी अमला इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। बता दें कि इस साल साढे 42 हजार हेक्टेयर में किसानों के द्वारा धान की फसल बोई गई है। कम बारिश होने के कारण इस बार किसानों को धान की फसल में सिंचाई को लेकर खासी दिक्कते आई है। ट्यूबवेल और नहर के पानी के जरिए किसानों ने जैसे-तैस करके धान की फसल को खड़ा कर लिया, लेकिन अब धान की फसल में लट का रोग लग गया है। इस रोग का नाम स्टेम बोरर बताया जा रहा है। यह रोग धान की फसल को चट कर रहा है। किसानों ने बताया कि यूं तो लट का प्रकोप कई जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा टेहला, जमूर्दी, गुरनावदा, सोंईकलां, नयागांव, ढोढपुर, लाथ, तलावड़ा, राडेप तथा बडौदा क्षेत्र के कई गांवों में लट का प्रकोप धान की फसल में साफ देखा जा सकता है, जहां लट के प्रकोप के कारण धान की फसल बाली सूख गई है। किसानों ने बताया कि इस रोग से फसल को 50 प्रतिशत के आसपास नुकसान पहुंच रहा है।

कीटनाशक दवाएं भी बेअसर

किसानों ने बताया कि लट के प्रकोप के कारण धान की फसल नष्ट होती जा रही है। हालांकि लट के प्रकोप से धान को बचाने के लिए कई तरह की कीटनाशक दवाओं का छिडकाव किया जा रहा है, लेकिन सभी कीटनाशक दवाएं बेअसर साबित हो रही है। चिंतित किसानों का कहना है कि जल्द ही कोई कारगर उपाए नहीं हुए तो धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और किसान बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में कृषि विभाग के मैदाली अमले को क्षेत्र में आकर किसानों को कारगर उपाए बताने चाहिए, ताकि धान की फसल को बचाया जा सके।

लट के प्रकोप के कारण अब तक 50 प्रतिशत धान की फसल प्रभावित हो चुकी है। महंगी से महंगी कीटनाशक दवाओं का छिडकाव कर रहे है, लेकिन दवाओं का भी कोई असर नहीं हो रहा है। विभागीय मैदानी अमला भी गायब है। ऐसे में क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

गिर्राज जाट
किसान टेहला

हमारे क्षेत्र में ज्यादातर खेतो में खड़ी धान की फसल में लट का प्रकोप है, इस प्रकोप के कारण धान की फसल चौपट हो रही है। जल्द ही कोई कारगर कदम उठाए नहीं गए तो फसल पूरी तरह तबाह हो जाएगी। प्रशासन को इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।

देवेन्द्र शर्मा
किसान लाथ

मैदानी अमले को क्षेत्र में भेजकर नुकसान का पता करवाया जाएगा और किसानों को कृषि वैज्ञानिकों के जरिए फसल बचाव के कारगर उपाए भी बताए जाएंगे।

पी गुजरे,उप संचालक, कृषि विभाग,श्योपुर

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ने अपने 60 वें स्थापना दिवस पर नवाजा

आदिवासी बिस्सो बाई और रामकिशोर को कृषक फेलो सम्मान

बैतूल। जागत गांव हमार

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ने अपने 60 वें स्थापना दिवस के अवसर पर आदिवासी महिला कृषक बिस्सो बाई धुर्वे, ग्राम धाड़गांव, घोड़ाडोंगरी को कृषि से आय में वृद्धि के लिए अपनाए गए एकीकृत कृषि माड्यूल के लिए एवं रामकिशोर कहार, ग्राम सिलपटी, शाहपुर को मशरूम, इसका बीज (स्पान) प्रसंस्करण एवं मशरूम उत्पादन को आदिवासी महिला कृषकों के मध्य लोकप्रिय बनाकर उनकी आय वृद्धि के लिए किए गए कार्यों के लिए कृषक फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। आभासी स्वरूप में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पीके मिश्रा, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय समन्वयक नाहेप कास्ट परियोजना आईसीएआर नई दिल्ली डॉ. अनुराधा अग्रवाल, के साथ-साथ अधिष्ठाता कृषि संकाय डॉ. डी खरे, संचालक विस्तार सेवाएं डॉ. डीपी शर्मा, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय डॉ. पीबी शर्मा एवं राज्यभर के कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि महाविद्यालयों के वैज्ञानिक, अधिकारी, विद्यार्थी आदि जुड़े हुए थे। उक्त कृषकों को कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल में केन्द्र के प्रमुख डॉ. व्हीके वर्मा द्वारा शॉल श्रीफल एवं प्रषस्ति पत्र प्रदान किया गया। रामकिशोर कहार ने इस केन्द्र पर मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर मशरूम बीज, ताजा मशरूम प्रसंस्करण आदि कार्य सफलतापूर्वक करके अपनी आय वृद्धि में सफलता पाई। बायफ अशासकीय संस्था से संबद्ध कृषक बिस्सो बाई द्वारा एकीकृत कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन, फल सब्जी उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन आदि कार्य किए गए हैं। जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय के संचालक विस्तार सेवायें द्वारा सम्मानित कृषकों को बधाई दी एवं उनके कार्यों की पशंसा की।

लखनऊ के ष्टस्स्ञ्द्ध में तैयार हुआ हेलो मिक्स

अब ऊसर जमीन पर भी लहलहाएगी फसल वैज्ञानिकों ने विकसित किया जैव फार्मुलेशन

लखनऊ। जागत गांव हमार

लखनऊ स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआई) के वैज्ञानिकों ने ऊसर भूमि में सुधार के लिए एक जैव फार्मुलेशन विकसित की है, जिससे ऊसर भूमि में अच्छी पैदावार और रासायनिक उर्वरकों की जरूरत कम होगी। इस फार्मुलेशन का नाम हेलो मिक्स है, और इसमें लवण सहिष्णु जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है, जो खेतों में उपज को बढ़ावा देते हैं और ऊसर भूमि की खेती को बेहतर बनाते हैं। इस तरल जैव-फार्मुलेशन के उपयोग से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और जिंक की बचत हो सकती है, जिससे ऊसर मृदा में फसलों के लिए उपयोगी तत्व मिल सकते हैं। ऊसर खेती में सुधार और उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है इससे ऊसर में किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है। खासकर वे जगहें जहां लवण के कारण ऊसर भूमि है। सीएसएसआरआई लखनऊ के मुख्य वैज्ञानिक संजय अरोड़ा ने बताया कि भारत में कुल 67 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता से प्रभावित है और इसमें से 13 लाख हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश में है। इसे खनिज जिप्सम के साथ जैविक उर्वरकों का उपयोग करके सुधार किया जा रहा है। आज के समय में फसलों के उपयोग के लिए खनिज जिप्सम एवं जैविक उर्वरकों की उपलब्धता कम होती जा रही है। लेकिन हैलो मिक्स नामक जैव-फार्मुलेशन से सुधार करके अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है।

उर्वरकों की होगी बचत

डॉ. अरोड़ा ने बताया कि तरल जैव-फॉर्मूलेशन हैलो मिक्स में लवण सहिष्णु जीवाणुओं की उचित संख्या होती है जो कि वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को एकत्र कर पौध वृद्धि करते हैं साथ ही इस तरल जैव-फॉर्मूलेशन में फास्फोरस एवं सूक्ष्म पष्क तत्व जिंक घुलनशीलता में वृद्धि करने वाले लवण सहिष्णु जीवाणु हैं जो पौधे को इन तत्वों को उपलब्ध करातें हैं। इन जीवाणुओं से फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है। ऊसर भूमि में धान, गेहूं, चारा, सब्जी की फसलों एवं तिलहन फसलों आदि के लिए इस जैव-फॉर्मूलेशन के प्रयोग करने से 15-20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 से 15 किलोग्राम फास्फोरस एवं 2-4 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर की बचत हो जाती हैं। इससे ऊसर मृदा में फसलों पर वातावरण का अनुकूल प्रभाव भी पड़ता हैं इसके जीवाणु जड़ों के पास की मृदा में रासायनिक पोषक तत्व उपलब्ध करातें हैं। यह पौधों की जड़ों में होने वाली कवक जनित बीमारियों से भी बचाते हैं। परिणामस्वरूप पौधे स्वस्थ रहते हैं एवं पैदावार में भी वृद्धि होती है।

15 फीसदी बढ़ जाएगी पैदावार

डॉ. अरोरा ने एक चर्चा के दौरान बताया हैलो-मिक्स तरल जैव-फॉर्मूलेशन लवण सहिष्णु जीवाणुओं के कंसोर्टिया के प्रयोग से धान एवं गेहूं की फसलों में औसतन 12 से 14 प्रतिशत तक की वृद्धि पायी गयी। साथ ही ऊसर मृदा के पीएच मान में 9.7 से घटकर 8.9 तक की कमी देखी गयी। इसके उपयोग से किसानों की आमदनी में धान में 2.31 तथा गेहूं में 2.59 तक औसत लाभ वृद्धि प्राप्त हुई। बीते 6 वर्षों में लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, सुल्तानपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, आगरा और इटावा के किसानों ने दोनों मौसमों रबी एवं खरीफ में लगभग 3500 एकड़ ऊसर भूमि में धान, गेहूं, सरसों, बैंगन, फूलगोभी, मटर, टमाटर एवं गन्ना की फसल में प्रयोग कर लाभ प्राप्त किया एवं गुजरात और बंगाल की लवण युक्त भूमि में लाभ मिला है।

किसानों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

हैलो मिक्स ऊसर भूमि वाले किसानों को उपलब्ध हो इसके लिए जैव-फॉर्मूलेशन तकनीक को एग्रीइनोवेट इंडिया, नई दिल्ली के माध्यम से मैसर्स आई पी एल बायोलोजीकल्स लिमिटेड, गुरुग्राम, को वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन और विपणन के लिए लाइसेंस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके लिए कंपनी की तरफ से हैलोमिक्स पूरी विधि पर प्रशिक्षण लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 25 से 29 सितंबर को लखनऊ स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के अन्तर्गत क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक और तकनीक की खोज करने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉ. संजय अरोड़ा एवं डॉ. यशपाल सिंह द्वारा दिया गया।

दुनियाभर के छात्र सीखेंगे जल संरक्षण की नई तकनीक

सूखे के लिए चर्चित बुंदेलखंड में खुलेगा दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय

लखनऊ। जागत गांव हमार

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है, जो कि करीब 25 एकड़ जमीन पर बनकर तैयार होगा। इस विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों के साथ-साथ विदेशी छात्रों को भी जल संरक्षण की शिक्षा व नई तकनीकों के बारे में सिखाया जाएगा।

गौरतलब है कि इस जल विश्वविद्यालय को पर्यावरण वैज्ञानिक प्रो. रविकांत पाठक और पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडेय के पहल पर शुरू किया जा रहा है। वहीं, इस काम के लिए पूर्व जिलाधिकारी डॉ. चंद्रभूषण ने उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। मालूम हो कि जल विश्वविद्यालय में जल संकट से निपटने के साथ बच्चों के भविष्य को भी बनाया जाएगा तो ऐसे में आइए आज दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय की पहल करने वाले उमाशंकर पांडेय के बारे में जानते हैं, इसके अलावा इन्होंने कैसे इस विश्वविद्यालय को बनाने के बारे में सोच।

कौन हैं उमाशंकर पांडेय

साल 2023 के पद्मश्री से सम्मानित उमाशंकर पांडेय का नाम जल विश्वविद्यालय से जुड़ा है। बता दें कि यह एक सोशल वर्कर हैं, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के बांदा जिले के जखनी में रहते हैं। यह अपने क्षेत्र में जल संकट की परेशानी को लेकर अपना अहम योगदान देते रहते हैं। बता दें कि यह युवावस्था में ही विकलांग हो गए और इनका जीवन बहुत ही ज्यादा संघर्षों से भरा हुआ रहा है। हालांकि, विकलांग होने के बाद भी इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के चलते यह आज देशभर में 'जल योद्धा' के नाम से जाने जाते हैं। भविष्य में पानी की दिक्कत तों को देखते हुए और लोगों को जागरूक करने के लिए इन्हीं की पहल से भारत में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है।

उमाशंकर ने बनाया जल ग्राम

बुंदेलखंड के ज्यादातर गांव सूखे की समस्या से जूझ रहे थे। उमाशंकर का गांव जखनी भी पानी की परेशानी से काफी लंबे समय से झूझ रहा था। ऐसे में उमाशंकर पांडेय ने अपने गांव में जल ग्राम बनाने का फैसला लिया और जल संकट को दूर करने का काम शुरू कर दिया। अपने इस काम में इन्होंने कड़ी मेहनत की और वह सफल भी हुए। जैसे ही उनके गांव में जल ग्राम बनकर तैयार हुआ उमाशंकर के द्वारा पूरे किए गए इस कार्यों को पूरे देश में सरहाया गया। उमाशंकर के अनुसार, अपने गांव में जल ग्राम बनाने के लिए उन्होंने लगभग 2,000 बीघे में मेड़बंदी की थी। इनकी मेहनत के चलते आज इनका पूरा गांव पानी की परेशानी से मुक्त है।

उमाशंकर को मिले कई पुरस्कार

'जल योद्धा' उमाशंकर को उनके द्वारा किए गए काम को लेकर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें कृषक सम्मान राज्य स्तरीय सम्मान, रजत की बूंदें राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय संवैधानिक जल योद्धा सम्मान आदि अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं।

सद्ब्रद्ध5द्य3सद्ब्द्ध5द्य3द्ब्द्ध5ड्ढद्य

आलू की खेती के लिए किसान अपनाएं यह तरीका, होगी उम्मीद से बढ़कर आय

कन्नौज। आलू एक सदाबहार सब्जी होती है। किसान इसकी खेती काफी बड़े मात्रा में कर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला भी आलू की खेती के लिए जाना जाता है और यहां के लगभग सभी किसान आलू की व्यवसायिक खेती करते हैं। यहां के किसान आलू के बेहतर उत्पादन के लिए सहफसली तरीके से खेती करते हैं, इससे आलू के पौधों को दूसरी फसल से सुरक्षा मिल जाती है और उनका उत्पादन भी बढ़िया हो जाता है। इस तरीके से खेती करने पर यहां के किसानों की पैदावार बेहतर होने लगी है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी है। आप भी इस सहफसली तरीके से खेती कर आलू का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको इसकी खेती के तरीके के बारे में बताते हैं-

क्या होती है सहफसली खेती- सहफसली खेती में दो यानी मुख्य फसल एवं सहफसल की खेती एक साथ की जाती है। इन फसलों की खेती करते समय आप एक की किस्म की फसल की बोवनी नहीं कर सकते हैं और इन दोनों फसलों का का पोषक तत्व ग्रहण का स्तर अलग हो और एक फसल की छाया दूसरी फसल पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए।

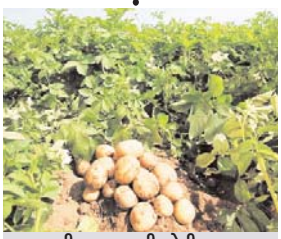

आलू की सहफसली खेती

आलू की बोवनी के साथ आप सब्जियों का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर लौकी, कद्दू, तोरई और नीबू जैसी फसलों के साथ आलू की सहफसली खेती की जा सकती है। इसमें आलू की फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। सर्दियों में आलू की फसल पर पाला पड़ने का खतरा रहता है। ऐसे में सहफसली पौधों के पत्ते से आलू को सर्दी से बचाया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, किसान अपने खेतों में पूरे मानकों को ध्यान में रखते हुए ही सहफसली फसल की खेती करें तभी आलू की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकेगी।

रोगों से बचाव

सर्दियों के मौसम में कोहरा पड़ने के कारण आलू की फसल में झुलसा जैसे रोग लग जाते हैं। ऐसे में किसान इस रोग से निजात पाने के लिए रीडोमील एमजेड-78 नामक दवा को दो ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं।

तापमान की आवश्यकता

आलू की बोवनी के लिए न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस की जरुरत होती है। अक्टूबर के शुरुआती दिनों में तापमान में गिरावट रहती है इस समय बुवाई करने से आलू के बीज नष्ट होने की आशंका रहती है। आप मुख्य रूप से कुफरी, गरिमा, कुफरी ख्याति, अशोका, सूर्य और पुखराज जैसी आलू के किस्मों की खेती कर सकते हैं। यह प्रजातियां 70 से 80 दिनों में तैयार हो जाती हैं। आप अपनी मिट्टी का परीक्षण करने के बाद आलू की किस्म का चयन करें।

बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश ने जीते दो अवार्ड

शिव शेखर शुक्ल ने कहा- एकजुट प्रयासों से मध्यप्रदेश को विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अग्रणी बनाएंगे

पन्ना के मडला ग्राम को स्वर्ण और सीधी के खोखरा ग्राम को मिला कांस्य पदक

भोपाल। जागत गांव हमार

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश ने फिर शीर्ष स्थान हासिल किया गया है। प्रदेश के ग्राम मडला और खोखरा 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुने गए हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम् कन्वेंशन सेंटर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पन्ना के मडला ग्राम को स्वर्ण श्रेणी और सीधी के खोखरा ग्राम को कांस्य श्रेणी में सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह में सचिव, पर्यटन, भारत सरकार वी. विद्यावती द्वारा प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की ओर से अपर प्रबंध संचालक विवेक श्रोत्रिय और संचालक कौशल डॉ. मनोज कुमार सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किया। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने ग्रामीण परियोजना विकास में प्रयासरत सभी अधिकारियों और सहभागी संस्थाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एकजुट प्रयासों से मप्र को विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अग्रणी बनाएंगे।

उल्लेखनीय है कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होम-स्टे के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 795 ग्रामों द्वारा आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से 35 ग्रामों को स्वर्ण श्रेणी में नामांकित किया गया। इन 35 ग्रामों में से शीर्ष 5 ग्रामों को स्वर्ण श्रेणी में सम्मानित किया गया, जिसमे मध्यप्रदेश का मडला ग्राम शामिल है।

प्राकृतिक सौंदर्य चयनित ग्रामों की विशेषता

पन्ना का मडला गांव, खूबसूरत केन नदी के किनारे स्थित है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व का एक गेट भी है। सीधी का खोखरा गांव, संजय दूबरी टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में स्थित है7 दोनो गांव ग्रामीण पर्यटन भ्रमण, होम-स्टे अनुभव, स्थानीय भोजन, कला और शिल्प में अनूठे हैं। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य इन ग्रामों की विशेषता है।

रिस्पोंसिबल टूरिज्म मिशन की ग्रामीण पर्यटन परियोजना

मप्र पर्यटन बोर्ड न केवल पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्यरत है, अपितु संतुलित और संवहनीय पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। यह सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम कर मप्र को सम्पूर्ण पर्यटन अनुभव कराने वाले गंतव्य के रूप में स्थापित करता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख टूरिज्म बोर्ड द्वारा रिस्पोंसि-बल टूरिज्म मिशन का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मप्र को विभिन्न सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं के कारण बघेलखंड, बुंदेलखंड, चंबल, मालवा, निमाड़ और महाकौशल जैसे छह प्रमुख सांस्कृतिक अनुभव क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों में प्रचलित पर्यटन स्थलों के समीपस्थ 100 ग्रामों में ग्रामीण पर्यटन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन ग्रामों में स्थानीय भ्रमण, स्थानीय वास्तुकला आधारित आवास, गैर रासायनिक परंपरागत भोजन, कला एवं शिल्प, स्थानीय भ्रमण, सुविधाजनक आवास, स्थानीय भोजन, स्थानीय सांस्कृतिक अनुभव तथा लोकगीत, लोक नृत्य, खेल-कूद, पूजा, उत्सव एवं त्योहारों का अनुभव, कला एवं हस्तकला का अनुभव एवं पर्यटन की आवश्यकतानुसार स्थानीय लोगों का कौशल उन्नयन जैसे 6 प्रमुख अंगों के लिए ग्रामीण पर्यटन अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। मडला और खोखरा गांव ग्रामीण पर्यटन परियोजना के तहत नवीन विकसित गांव हैं।

पिछले साल भी सर्वे कार्य नहीं किया गया

सोयाबीन की फसल खराबः किसान प्रशासन से लगा रहे सर्वे की गुहार

सीहोर। जागत गांव हमार

इस समय किसान खराब सोयाबीन फसल लेकर कलेक्टोरेट पहुंच रहे हैं। इस वर्ष बारिश से फसल पूरी तरह खराब हो गई है। हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित फसल वही हुई है जहां पहले बोवनी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में किसान खेतों में फसल को काटकर फेंक रहे हैं। खेतों में खड़ी फसल में ना फूल हैं और ना ही फली दिखाई दे रही है। पूर्व में बारिश नहीं होने के कारण और अब अतिवृष्टि से फसल खराब हो गई है। इसको लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था। ग्राम सिराड़ी और निपानिया खुर्द के किसानों ने कलेक्टर से संबंधित एक ज्ञापन तन्मय वर्मा को दिया। डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि जैसे ही पटवारियों की हड़ताल खत्म होगी समस्त किसानों का कार्य कराया जाएगा। किसानों का कहना है कि गत वर्ष भी सर्वे कार्य नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज बोले

सोयाबीन की फसल में नुकसान का होगा सर्वे, मिलेगी राहत

इधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यदि सोयाबीन की फसल में कहीं नुकसान हुआ होगा तो जल्दी ही सर्वे करवाकर राहत राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को समृद्ध और देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। सीएमसीहोर जिले के मरदानपुर गांव में 46 करोड़ 22 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि-पूजन तथा लोकार्पण करने के बाद जनसमुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनमानस का असीम आशीर्वाद प्रदेश के विकास और लोगो के जनकल्याण की योजनाएं बनाने की शक्ति देता हैं। विकास के लिए धन की कमी नहीं होती जबकि दूसरी सरकारें पैसा नही होने का रोना रोती हैं।

रायसेन की महिला पंचायत पदाधिकारियों का किया गया प्रशिक्षित

भोपाल। जागत गांव हमार

राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली एवं अटल बिहारी वाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 'सी इज गेम चेंजर' विषय पर रायसेन जिले की ग्राम पंचायतों की महिला जन-प्रतिनिधियों का तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण गत दिवस क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में संपन्न हुआ।

प्रशिक्षण में मप्र राज्य आजीविका मिशन के अमित खरे ने स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण एवं संवहनीय आजीविका में ग्राम पंचायतों की भूमिका के बारे में बताया। ऋचा मिश्रा, वरिष्ठ सलाहकार, एआईजी-जीपीए ने नेतृत्व कौशल विषय पर चर्चा की। डॉ. सुप्रभा पटनायक, प्रमुख सलाहकार तथा संस्थान के सलाहकार गौरव खरे, भागवत अहिरवार एवं अमिताभ श्रीवास्तव द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिए गए। रायसेन जिले की महिला सरपंचों ने इस प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताया और राष्ट्रीय महिला आयोग एवं सुशासन संस्थान का आभार व्यक्त किया।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)